किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम

किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री की सात सूत्री कार्ययोजना

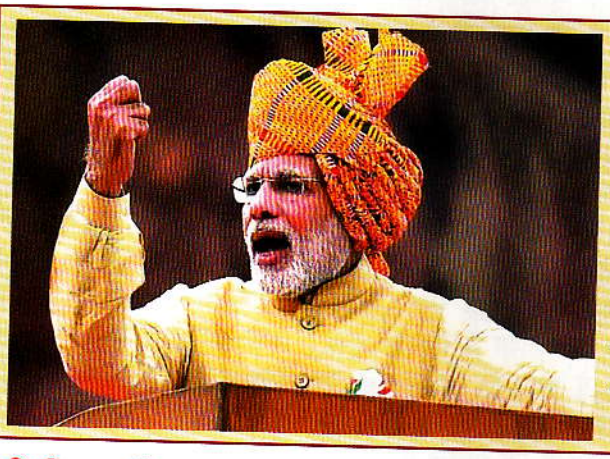

- 'प्रति बूंद, अधिक फसल' के उद्देश्य को लेकर बड़े पैमाने पर निवेश के साथ सिंचाई पर अधिक फोकस।
- क्वालिटी बीजों और पोषकों की उपलब्धता।
- भंडारगृह, कोल्डचेन और भंडारण सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर निवेश।
- खाद्य प्रसंस्करण के जरिए मूल्य संवर्धन।
- फसल बीमा योजनाओं के जरिए आपदा प्रबंधन।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना तथा
- सहायक गतिविधियों जैसे मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा।

कृषि विकास की दर

कृषि वृद्धि दर	2012–13	2016–17
	1.2 प्रतिशत	4.4 प्रतिशत

'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एवं खरीद

- वर्ष 2016–17 में खरीफ दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में व्यापक वृद्धि। अरहर का एमएसपी 4625 रुपये से बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति क्विंटल; उड़द का एमएसपी 4625 से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का एमएसपी 4850 रुपये से बढ़ाकर 5250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।
- **रबी दलहनों के एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि**– चने का एमएसपी 3500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर का एमएसपी 3400 रुपये से बढ़ाकर 3950 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।
- दालों के बफर स्टॉक को पहली बार 1.5 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया गया ताकि दालों की कीमतों में उतार–चढ़ाव को रोका जा सके।
- लगभग 19.90 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद की गई।
- 17 अप्रैल, 2017 तक रबी सीज़न के दौरान 229.61 लाख टन गेहूं की खरीद।

'उर्वरक

नीम कोटेड यूरिया– अब यूरिया के लिए कोई लाईन नहीं

- सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन अनिवार्य बनाया गया।
- स्वदेशी यूरिया और आयातित यूरिया की शत–प्रतिशत नीम कोटिंग का लक्ष्य हासिल।

नई यूरिया नीति 2015 के तहत

- यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
- कृषि से भिन्न उद्देश्यों में अत्यधिक सब्सिडी वाले यूरिया के इस्तेमाल की मात्रा घटाकर नगण्य की गई।
- विभिन्न फसलों के उत्पादन में 5 से 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन

- 2015–16 के दौरान बिना किसी अतिरिक्त लागत के 245 लाख एलएमटी यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन, इसे वर्ष 2016–17 में सफलतापूर्वक बरकरार रखा गया।
- उर्वरक सब्सिडी बकाया को निपटाने के लिए वर्ष 2017–18 के बजट में 10,000 करोड़ रुपये की विशेष बैंकिंग व्यवस्था को मंजूरी।
- नई यूरिया नीति 2015: 1 जून, 2015 से 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी।
- इससे हर साल 20 लाख/एलएमटी अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होगा और सरकार को करीब 5000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
- यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा, यूरिया का अपने देश में अधिकतम उत्पादन और सब्सिडी को सुसंगत बनाना।
- वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए घरेलू यूरिया क्षेत्र को बढ़ावा। इससे आयात व्यय और विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

बंद पड़ी उर्वरक यूनिटों को पुनः चालू करना

देशभर में उर्वरक की मॉडल खुदरा दुकानें

- यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता के लिए 2016–19 के बीच के तीन वर्षों में उर्वरक की 2000 मॉडल खुदरा दुकानें खोली जाएंगी।
- वर्ष 2016–17 में उर्वरक की 1800 मॉडल खुदरा दुकानें खोली गईं।

किसानों को ज्यादा ऋण की सुविधा

- वर्ष 2016–17 में किसानों को लगभग 9 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए गए और वर्ष 2017–18 में इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया।

'ई–नाम

- प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल, 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का शुभारंभ किया गया।
- ई–नाम के जरिए किसानों को अपनी फसलों की बेहतर कीमतें मिल सकेंगी।
- किसानों के लिए सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई–ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 585 विनियमित बाजारों को एकीकृत करेंगे।
- 13 राज्यों में 417 मंडियां सीधे ई–नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं।
- प्रत्येक मंडी को 'ई–नाम' के ढांचे की स्थापना के लिए 75 लाख रुपये की राशि आवंटित।
- 41.91 लाख से भी ज्यादा किसान और 89,312 व्यापारी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं।
- 24 अप्रैल, 2017 तक 16,916.81 करोड़ रुपये मूल्य के कृषि उत्पाद का लेन–देन ई–नाम प्लेटफॉर्म पर हुआ।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- उवर्रक के उपयोग और इससे जुड़े खर्चों में कमी के लिए यह योजना लांच की गई।
- 2018 तक सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का लक्ष्य; अभी तक 6.93 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी; 25 अप्रैल, 2017 तक मिट्टी के 2.80 करोड़ नमूनों का संग्रह किया गया।
- 2014–17 के बीच 8572 मिनी लैबों सहित 9063 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं मंजूर की गईं, जबकि 2011–14 के दौरान इसकी संख्या मात्र 15 थी।

फसल बुआई का क्षेत्र बढ़ा

- रबी और खरीफ की फसल बुआई के क्षेत्रफल में खासी बढ़ोतरी।

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य के साथ 2014–17 के दौरान योजना के तहत 17.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित की जाएगी।
- 'हर खेत को पानी' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 5189 करोड़ रुपये के बजट को बढ़ाकर 7377 करोड़ रुपये किया गया।
- बजट 2017–18 में दीर्घकालिक सिंचाई कोष को 100 प्रतिशत बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया गया।
- 'प्रति बूंद अधिक फसल' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5000 करोड़ रुपये का समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया जाएगा।
- सूक्ष्म सिंचाई के लिए 'प्रति बूंद अधिक फसल' के अंतर्गत 2014–17 के दौरान 15.86 लाख हेक्टेयर भूमि को इसके अंतर्गत लाया गया।

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- किसानों के लिए अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर तथा अतिरिक्त लाभ वाली फसल बीमा योजना की सुविधा।
- फसल बीमा के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब तक की सर्वाधिक वित्तीय सहायता का प्रावधान।
- अगले 2 से 3 साल में फसल बीमा कवरेज को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना।
- खरीफ 2016 के दौरान 23 राज्यों में इसका कार्यान्वयन, 3.90 करोड़ किसानों ने पॉलिसी ली और 1,41,883.30 करोड़ रुपये की बीमा राशि का बीमा हुआ।
- रबी 2016–17 के दौरान अब तक 1.67 करोड़ किसानों ने 71728.59 करोड़ रुपये की बीमा राशि का बीमा हुआ।

'आपदा में किसानों को सहायता

- आपदा में किसानों को राहत अब न्यूनतम 50 प्रतिशत फसल नुकसान होने की जगह न्यूनतम 33 प्रतिशत नुकसान पर ही मिलेगी।
- विभिन्न मदों के तहत राहत राशि 1.5 गुना बढ़ाई गई।
- अतिवृष्टि के फलस्वरूप खाद्यान्न को नुकसान होने पर पूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाएगा।
- मृतक के परिवारों को बतौर सहायता अब 2.5 लाख रुपये के बजाय 4 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- 2010–15 के लिए 33,580.93 करोड़ रुपये की तुलना में 2015–20 के लिए एसडीआरएफ संबंधी प्रावधान को 82 प्रतिशत बढ़ाकर 61,220 करोड़ रुपये किया गया।

'गन्ना किसानों को सीधी सब्सिडी

- गन्ना किसानों के खातों में सब्सिडी सीधे भेजी गई।
- गन्ना सब्सिडी के जरिए किसानों को उनकी बकाया राशि का भुगतान; यह बकाया राशि पहले की तुलना में काफी कम हो गई है।

गन्ना की बकाया राशि जारी

- वर्षों से उत्तर भारत में गन्ना किसानों को गन्ने की कीमतों का बकाया भुगतान नहीं हुआ। इसीलिए सरकार ने उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई।

गन्ने का मूल्य बढ़ाया

- 2017–18 के लिए चीनी मिलों द्वारा उचित देय और लाभकारी मूल्य को मंजूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने 2017–18 के लिए। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य 255 रुपये प्रति क्विंटल तय करने को मंजूरी प्रदान की गई।

परंपरागत कृषि विकास योजना

- जैविक खेती को बढ़ावा। 2015–18 के दौरान जैविक खेती के दायरे में 2 लाख हेक्टेयर भूमि वाले 10,000 क्लस्टरों को लाया जाएगा;
- राज्य सरकारों द्वारा अब तक 7186 क्लस्टर विकसित किए गए।
- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला–2015–18 के लिए 400 करोड़ रुपये।

नीली क्रांति

- **मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रांति;** नीली क्रांति के अंतर्गत सभी मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर योजना की पुनर्संरचना की गई।
- बचत–सह–राहत के अंतर्गत प्रति वर्ष औसतन 4.90 लाख मछुआरे लाभान्वित। प्रतिवर्ष औसतन 48.65 लाख मछुआरों का बीमा।
- बजट का प्रावधान 2016–17 के 147 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017–18 में 401 करोड़ किया गया।
- मछली उत्पादन 2012–14 में 186.12 लाख टन से बढ़कर 2014–2016 में 209.59 टन हुआ।
- दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी अपंगता के लिए बीमा कवच राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- स्वदेशी गौ–नस्ल के अनुरक्षण एवं विकास के साथ–साथ दूध उत्पादन और डेयरी विकास का लक्ष्य।
- 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की गई है और 41 बुल मदर फार्म का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- 3629 सांडों को प्राकृतिक सेवा के लिए शामिल किया गया।
- दूध का उत्पादन 155 मीट्रिक टन (2015–16) से वर्ष 2016–17 में बढ़कर 163.74 मीट्रिक टन (अनु.) हुआ।
- दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2015–16 के 340 ग्राम/दिन में बढ़कर 2016–17 में 365 ग्राम/दिन हुई।
- पशु चिकित्सा कॉलेजों की संख्या 36 से बढ़कर 52 हुई।

किसान चैनल (24X7)

- किसानों के लिए समर्पित 24X7 किसान टीवी चैनल।